



VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2369)

Name of Candidate	Prateek choudhary		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1017622
Center	online	Date	05/08/24

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **HINDI & ENGLISH**.
इसमें बीस प्रश्न हैं हिन्दी और अंग्रेजी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Is student recommended for One-to-One mentoring?

Recommended

Strongly Recommended

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp. Punjab & Sind Bank), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VisionIAS

All the Best

For one-to-one mentoring session on this copy, call us at 7042691891 or send an email to appointment@visionias.in

Q1.

भारत के परिवहन क्षेत्र का ऊर्जा संक्रमण जो 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हेतु भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, कई बाधाओं का सामना कर रहा है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The energy transition of India's transport sector, significant to fulfil India's commitment to net-zero emissions by 2070, faces several hurdles. Discuss. (Answer in 150 words) 10

ऊर्जा संक्रमण से अभिप्राय ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों (जीवाश्म ईंधन) से ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ना, जिसमें परिवहन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन में 14% का योगदान देता है।

परिवहन क्षेत्र के प्रमुख चुनौतियाँ

- ① ऊर्जा उत्पादन गहन परिवहन प्रणाली (14% ऊर्जा उत्पादन के लिए उपरदायी)
- ② पुरानी प्रौद्योगिकी व पुराने वाहन (परिवहन मांग में अनुमान 50% से अधिक वाहन 25 साल से अधिक पुराने)।
- ③ अनुसंधान ईंधन की लागत (धूम्र प्रदूषण में अधिक योगदान)
- ④ जीवाश्म ईंधन आधारित प्रणाली (80% ऊर्जा मांग आधारित आधारित)

- ⑤ EV वाहनो की सीमित पहुँच (कुल वाहन बाजार का 1% ही EV वाहन) ।
- ⑥ कुशल रफा सर्विलनित् परिवहन प्रणाली अभाव (नीति आयोग अनुसार रेल्वे का मातृदुर्तव मे हिसरना 27% निम्न स्तर पर) ।

परिवहन क्षेत्र का महत्व - ① अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धताए

(100-26) अंतरगत पंचांभृत नक्षय (2030 तक ऊर्जा गहनता 55% कमी) ।

- ② परिवहन क्षेत्र (अर्थध्वस्या का मेरुदण्ड) व कुण्ड प्रभाव उद्योगि ।
- ③ परिवहन क्षेत्र स्वात्म्य (पर्यावरण) (पारिस्थितिकि इष्टिकेण) से भी महत्व ।

उठाये गये कदम - नेशनल मोबिलिटी मिशन प्लान

- फेम मोलना (EV वाहन प्रोत्साहन)
- नीति आयोग की परिवहन वि डार्कनीकरण रणनीति ।

परिवहन क्षेत्र जहाँ जसक उत्संजिन

योगदानकरा है वही आर्थिक क्रियात्मो का आधार है, जिले SDG-8 (जिन्मोफारी कुर्ग उपमोण) अनुसार परिवर्तन से अवश्यकरा है ।

Q2. मत्स्यन सन्धि पर WTO के समझौते में कुछ हानिकारक सन्धियों को प्रतिबंधित करने हेतु नियम निर्धारित किए गए हैं। विवेचना कीजिए। भारत के मत्स्यन क्षेत्र के लिए इस समझौते के क्या निहितार्थ हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

WTO's Agreement on Fisheries Subsidies lays out rules for prohibiting certain forms of harmful subsidies. Discuss. What are the implications of the agreement on India's fisheries sector? (Answer in 150 words) 10

हाल ही में जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में सम्पन्न WTO
संगठन की बैठक में जिनेवा पैरेज अंतर्गत
मत्स्य सहायिकी सम्बन्धित प्रवाधानों पर सहमति
बनाने का प्रयास किया गया, जो भारतीय मत्स्य क्षेत्र
से भी विपरीत रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

जिनेवा पैरेज अंतर्गत प्रवाधान —

- IUU (फिशिंग (unregulated illegal fishing))
से सम्बन्धित गतिविधियों पर रोक पर सहमति
- हानिकारक मत्स्य सहायिकी को प्रतिबन्धित
किया जाना।
- बॉटम ड्रैजिंग जैसी अत्यन्त मत्स्य पालन तकनीकों
पर रोक।

→ UN High Level (UN हाई ली) व विकास आर्थिक क्षेत्रों में स्पष्ट सीमांकन के आधार पर मध्यम पकड़ा जाता।

→ मध्यम जीव सीजन में (कीरिंग पर प्रतिबन्ध व निमज्ज)।

भारत के लिए निहितार्थ -

→ मध्यम सहाय्य नीति (साक्षात् किन्तु विमर्दीयता दायित्वों के विपरीत है)।

→ मध्यम सहाय्य की का असंगत बंधन (भारत वैश्विक विकसित देशों की तुलना आधी सहाय्य की ही प्रदान करता है)।

→ विवादास्पद मद्दत आवादी (10 करोड़ मध्यमपातक समुदाय मिलने 10% निर्धनता रेखा से नीचे)।

→ सर्वसम्पत्ति बनाने का सीमित प्रयास किया जाता।

जैसे कि भारत जैसे विकासशील देशों की मांगों को सम्बोधित नहीं करता। परिणामतः भारत वसने बाधित नहीं जो जैसे कि देश व 1970 अंतरगत मध्यम सहाय्य पर अधिक स्थायी सहाय्य की मांग करता है।

Q3.

यद्यपि पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना ने अनेक किसानों को लाभ प्रदान किया है, फिर भी इसे कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Although the PM-KISAN Scheme has provided benefits to numerous farmers, it continues to face several significant challenges. Discuss. (Answer in 150 words) 10

पीएम किसान योजना किसानों को प्रत्यक्ष लाभ
(प्रतिवर्ष प्रतिकिसान 6000 मासिक वार्षिक) पहुँचाने
के लिए प्रारम्भ की गयी एक महत्वपूर्ण
केंद्रीय क्षेत्र योजना है।

PM किसान के लाभ -

(1) किसानों के लिए
विविध कृषि संबन्धित व तरलता अभाव की
समस्याओं से निपटने में सहायक (नावटि अनुसंधान
50% किसान अनुसंधानिक कृषि क्षेत्र है)

(2) कृषि क्षेत्र में आवश्यक उपकरण खरीद
(बीज उपकरण) आदि में सहयोगी।

④ कमान अक्ट के विकट अनिश्चितता समाधान के रूप में।

⑤ किसानों का वित्तीय समावेशन के लिए समावेशन सुनिश्चित करना (राशि DBT से माध्यम से भेजा जाना)

⑥ इसमें अप्रत्याशित निवेश के रूप में (कृषक अपनी अवकृता अनुसार इस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं)

पीएम किसान सभा सुनौतियाँ -

① सीमित राशि (6000 अर्थात् ₹), राष्ट्रीय ग्रामीण योजना (उडीला) वास्तविक (बेसगोना) में अधिक राशि का प्रदान।

② केवल मूल्यवान् वाले कृषकें तक सीमित जबकि 50% ग्रामीण परिवारों के पास मूल्यवान् का अभाव (2011 जनगणना अनुसार)

③ समावेशन विच्छेदन कृषि (नाभायों पहचान राज्य सरकारों की जिम्मेदारी)

अतः पीएम किसान को अधिक समावेशी व दृढ़ बनाकर कृषकों की आम लोगना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

Q4.

भारत में पशुपालन को रूपांतरित करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकती है?
(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What role can digital technology play in transforming animal husbandry in India?
(Answer in 150 words) 10

राष्ट्रीय पशुजनगणना अनुसार 500 मि. पशु आबादी के साथ विश्व में सर्वाधिक पशुधन आबादी वाला देश है, जिसके रूपांतरण में डिजिटल प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकती है।

पशुपालन क्षेत्र में चुनौतियाँ —

- ① पशुधन सम्बन्धित विविध जानकारी (रोग, प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धित) जटा अभाव।
- ② वाणिज्यिक पशुपालन तुलना आजीविका आधारित पशुपालन की प्राथमिकता।
- ③ कृत्रिम गर्भाधान, नस्लसुधार, पशुस्वास्थ्य पर सीमित ध्यान दिया जाना।
- ④ पशुपालन सम्बन्धित अनुसंधान विकास सीमित है।

पशुपालन व डिजिटल प्रौद्योगिकी -

- ① पशुपालन सम्बन्धित विविध जानकारियों का डिजिटल डेटा बेस का निर्माण जैसे नकून स्वास्थ्य पत्रों का डिजिटलीकरण ।
- ② वाणिज्यिक पशुपालन (डोर, बिगजल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेलर्स के प्रयोग द्वारा पशुधन की निरन्तर निगरानी ।
- ③ पशु उत्पादों का डिजिटलीकरण द्वारा बेहतर विषयगत सुनिश्चित करना जैसे ई लता गोपालन पॉल्टन आदि ।
- ④ पशु स्वास्थ्य कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धित उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना ।

इस दिना प्रधानमंत्री कृषि सम्पदा योजना

राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान, विज्ञान सप्तहि डेन्ड राष्ट्रीय पशुधन कार्यक्रम जैसे नवान्कारी उपागमों से डिजिटल प्रौद्योगिकी उपयोग पर बत दिया जा रहा है ।

Q5.

भारत का पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण संरक्षण हेतु कृषि को संधारणीय बनाने के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

India's traditional knowledge offers solutions for making agriculture sustainable for environmental conservation. Illustrate with examples. (Answer in 150 words) 10

पारम्परिक ज्ञान सामान्यतः स्थानीय भाषा की शब्दों से संचित व्यवहारिक समाधानों का समाधान होता है, जो पर्यावरण हितकारी से अनुसृत होता है।

वर्तमान की प्रमुख समस्याएँ

- ① मृदा निम्नीकरण की समस्या (UNCAO अनुसार भारत की 43 मृदा निम्नीकृत हैं।)
- ② मृदा में NPK अनुपात (8:4:1) उच्चता।
- ③ वायुमय परिवर्तन से कीट की बढ़ती संख्या व खाद्य सुरक्षा का संकट।
- ④ कीट से पर्यावरणीय असंतुलन (कीटों की 14% जनसंख्या उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है।)
- ⑤ कीट व उन्नत निवेश व शोधों की असमता व सीमित उत्पादकता की समस्या।

पारम्परिक प्रणाली व स्मि संरक्षण -

① पर्यावरण अनुकूल इतिहास भण्डान
के प्राकृतिक स्मि को भण्डान (सुमाय पालेकर)
की अवधारणा।

② संधारणीय उत्पादन सुनिश्चित करना

उदा. बैरत की कुण्डनक धान प्रणाली
(आरे समुदाय जल से उत्पादन)

③ मृदा इतिहास से लाभदायक प्रणाली

उदा. उप्रसखण की वारहनाजी प्रणाली
(स्थानीय मोटे अनाज की 12 किमी का उत्पादन)

④ सिंचि की पारम्परिक प्रणाली भण्डान

उदा. बुन्देलखण की गवाब सिंचि प्रणाली

अतः उनको सिंचि पोषण पत्र

अनुरूप स्मि आधारित स्मि प्रणाली पर्यावरण
व खाद्यसुरक्षा (SDG-2) को सुनिश्चित कर सकती हैं।

Q6.

भारत में आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए।)

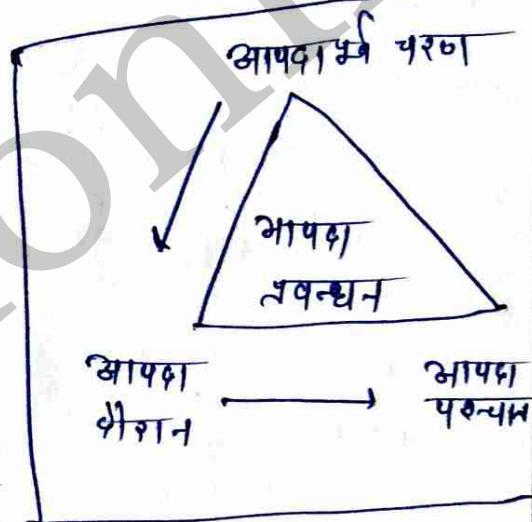
Comment on the role of media in disaster management in India. (Answer in 150 words)

10

आपदा प्रबंधन में समिप्राय आपदा से रोकथाम व उत्तरे प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अपनायी गयी आपत प्रणाली से है, मीडिया आपदा प्रबंधन के तीन चरणों में महती भूमिका निर्वहन करती है।

मीडिया की भूमिका व

आपदा प्रबंधन



① आपदा पूर्व चरण

② रोकथाम - आपदा के

सम्बन्ध में जानकारी ल्यानीस समाचार पत्रों, न्यूनतम के माध्यम से ।

आपदा प्रबंधन व मूमि उपयोग पैटर्न से लही उपयोग सम्बन्धित जानकारी देने में महत्वपूर्ण ।

उदा. डेरा बाद प्रबंधन में आपदा मीडिया कार्यक्रम में मीडिया की भागीदारी ।

② आपदा के दौरान -

- राष्ट्र बचाव कार्य में प्रशासन की जानकारी उपलब्ध कराने में मीडिया की भूमिका।
- कसे हुए लोगों की जानकारी व राष्ट्रबचाव कार्य की निष्पक्ष रिपोर्टिंग से पारदर्शिता जमावकेहता सुनिश्चित करने में।
- उदा. देवनाच बंद (2013) दौरान मीडिया जानकारी आधार पर राष्ट्र बचाव अभियान।

③ आपदा परन्चात - मीडिया की पुनःवहाती, परन्चात, पर अविष्य में विगरानी प्रणाली सुनिश्चित करने में।

उदा. नेपाल भूकम्प परन्चात स्थानीय आवादी के पुनःवास में मीडिया सहयोग के थापक अनुदान राशि प्राप्ति।

सबसे पहले आपदा जोखिम रणनीति व Early warning for AM अर्थात् की मीडिया भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए।

Q7.

औषधि विकास और विनिर्माण के संदर्भ में, प्रौद्योगिकी किम प्रकार भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग को रूपांतरित कर रही है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How is technology transforming India's pharmaceutical industry in terms of drug development and manufacturing? (Answer in 150 words) 10

भारत के अन्तर्गत भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल उद्योग परितंत्र है, जो वैश्विक जनसंख्या का उत्पादन में 20% योगदान देता है।

औषधि विकास विनिर्माण समग्र पुनर्निर्माण -

- ① भारत पेटेंट स्वामि के स्थान पर जनसंख्या उत्पादन शक्ति की रूप में पहचान।
- ② अनुसंधान विकास पर सीमित ध्यान (GDP का 0.67%) व्यय।
- ③ API (सक्रियता घटक) के लिए आयात निर्भरता (80-90% आयात चीन से किया जाता)
- ④ आधुनिक - आनुवंशिक संशोधन का अभाव।
- ⑤ नयी दवा निर्माण की उच्च लागत होना।

शोधगिरी व कपात्ररण (फार्मासो) —

- ① शोधगिरी उपयोग से अनुसंधान विकास को बढ़ावा दिया जाना संभव ।
- ② उन्नत शोधगिरी उपयोग द्वारा AP2 स्वच्छी निर्माण संभव ।
- ③ नवान्यार बढ़ावा देकर पेटेंट मुक्त दवा निर्माण संभव ।
- ④ उन्नत शोधगिरी सहित WHO के GMP (गुड मैनुफैचरिंग प्रैक्टिस) अपनाना सरल ।

इस दिशा में वल्ड ड्रग्स पार्क
पेरमजनसोधधि योजना व राष्ट्रीय बायोफार्मा
मिशन के साथ निरंतर अनुसंधान नवान्यार को
 बढ़ावा देने के प्रयास करना जाना चाहिए ।

Q8.

कृषि के साथ सौर ऊर्जा को संयोजित करने वाली एग्रीवोल्टाइक प्रणाली किस प्रकार भारतीय कृषि के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध हो सकती है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How can agrivoltaics, which combines solar energy with farming, be a game changer for Indian agriculture? (Answer in 150 words) 10

एग्रीवोल्टाइक प्रणाली कृषि क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन व भण्डारण में नवीकरणीय ऊर्जा व समाधान उपयोग पर आधारित है जैसे फील्ड कुलुम अलग-अलग सीवर पम्प योजना।

एग्रीवोल्टाइक प्रणाली एक गेम चेंजर रूप में

- ① कृषि क्षेत्र में लाभ उत्पन्न करने के साथ-साथ (150. लाभ उत्पन्न)
- ② सहायिकी के बिना काम करने में (4000000)
- ③ सहायिकी के बिना काम करने में (4000000)
- ④ सहायिकी के बिना काम करने में (4000000)

योजना अर्थात् विषयान ।

④ रुबि में सीवजनित निवेश में वृद्धि एगोवोलिड प्रणाली ऊर्जा व प्रजी गहन प्रणाली अिलल निवेश अधिउ ।

⑤ जीवांशम ईधन पर निर्भरत, उम व अतराहदीम प्रविबद्धताओ (पद्यांमृत लक्ष्य) प्राप्ति में लक्ष्योग ।

⑥ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में (सदा निम्नीकरण अल्लधिउ सिचारी के कारण)

अबोक फलवई समिति (समने की भाग को गुना करने के समन्धित) ने भी रुबि में प्रौद्योगिकी प्रयोग को गेम चेंजर रूप में वणिता दिया, जिसे रुपको को भाग्य को गुनी करने के लाय अतरत रुबि उत्पादन (SDG-2) सुनिश्चित किया जा सकता है ।

Q9.

क्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की संयुक्तता भारत के विभिन्न भागों में सामना की जा रही प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहायक हो सकती है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Can jointness of the Central Armed Police forces (CAPFs) help in tackling the major security challenges being faced in various parts of India? (Answer in 150 words)

10

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) केंद्रीय गृहमंत्रालय अंतर्गत कार्यरत वैधानिक बल है, जिसका अधिकतम सीमा सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

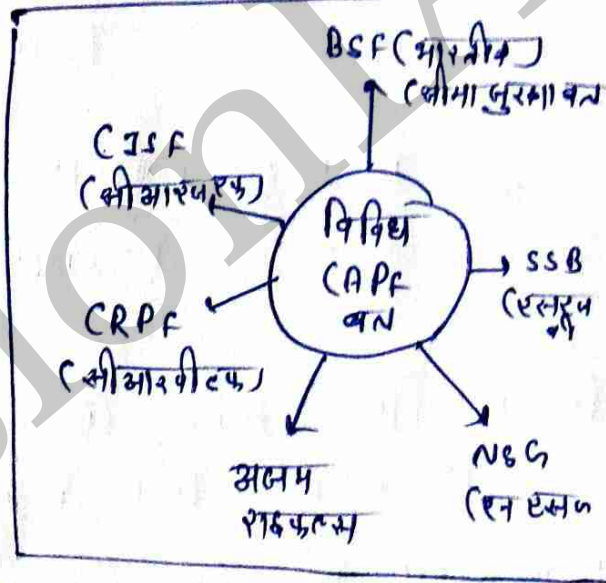
सुरक्षा चुनौतियाँ

① अलग-अलग क्षेत्रों की समस्या उदा. उश्क भातकेवाद ।

② सीमाप्रबंधन में अपेक्ष तस्करी

मादक अपराध तस्करी, संगठित अपराध की समस्या ।

③ उपररूर्व में अकारि की समस्या (मणिपुर संघर्ष)



संयुक्तता से समाधान -

- ① अंतरराष्ट्रीय समन्वय सुनिश्चित होने
आपरेकान अंतराष्ट्र-2 (भारत शामिल) मुख्य
अपेक्षित शकफलय भूमिका ।
- ② सीमापारवधन से संगठित अपराधों व
संयुक्त भातंकी विप्रपोषण ने संयुक्त
प्रति विकसित सहायोगी ।
- ③ अल्पचनता एकत्रण अपेक्षाकृत भारत हीना ।

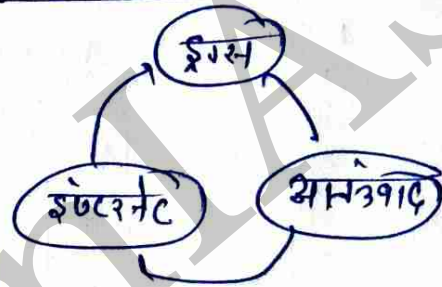
इस प्रकार संयुक्तता द्वारा
CAPA अधिक प्रकृता है साथ उमरती
समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ।

Q10.

ड्रग्स, इंटरनेट और आतंकवाद के बीच संबंध किस प्रकार भारत के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How has the linkage between drugs, internet, and terrorism emerged as a significant threat for India? (Answer in 150 words) 10

800 मि. इंटरनेट आबादी, गोल्डन ड्रीम व गोल्डन डारंग मह्य अव्यक्ति व वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट अनुसार भारत सबसे बड़ा ड्रग बाजार, जैसी प्रभावशाली समस्या भारत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।

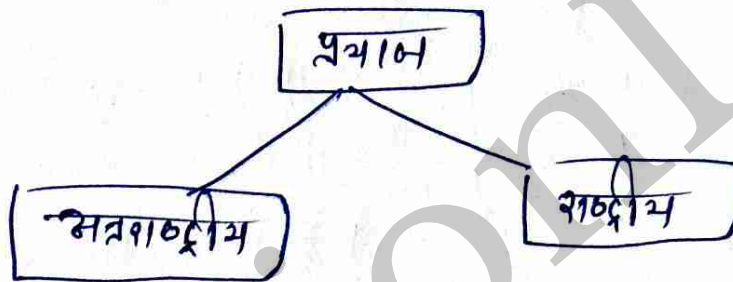


प्रभावशाली चुनौती

- ① इंटरनेट का उपयोग (विशेष रूप से) माध्यम से ड्रग तस्करी के लिए किया जाता है।
- ② सोशल मीडिया माध्यम से डाउन फ्रंटिंग का उपयोग आतंकी विप्लवों के लिए किया जाता है।

⑥ इस तस्वीर से प्राप्त आथवा आतंकी विमपौषण व लियार खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाता।

⑦ तस्वीर सम्बन्धित संगठित अपराधो को इन्टरनेट जैसी (वर्चुअल एसेस) का इस्तेमाल किया जाता।



- UNSC का दिल्ली घोषणा पत्र (आतंकवाद व अस्वस्थी प्रोधागिकी)
- वेब अगेस्ट टेररिज्म जैली पदन।
- FATF अन्तर्गत "No money for terror"
- NCOR (राष्ट्रीय नाकी समन्वय केन्द्र)
- सीमा सुरक्षा वना मध्य स्थानतन।
- भापरेकान समुहगत (नाकालिक अणुअस्त्रो सारा)

इस प्रकार बहुआयामी एजनीति अपनायी जाती नाहिए।

Q11.

भारत के अवसंरचना विकास के लिए एक निवेश मॉडल के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। PPP अवसंरचना की सभी निष्पादन संबंधी समस्याओं के लिए काम्यार क्यों नहीं है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of Public-Private Partnerships (PPP) as an investment model for India's infrastructure development. Why are PPPs not a panacea for all infrastructure-related performance problems? (Answer in 250 words) 15

अवसंरचना विभाग एक दीर्घवधि निवेश क्षेत्र है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही अब निजी सहयोग भी निमा जाग है अब इसे PPP मॉडल (सार्वजनिक निजी भागीदारी) खोजा जा रही है

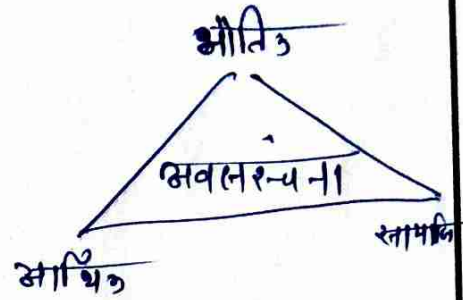
उदा. BOT मॉडल (Build Operate Transfer)
HAM मॉडल (Hybrid Annuity Model आदि)

अवसंरचना विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका -

(1) सरकार के सीमित ससांसध (राजकोषीय धारें GDP का 5% लगभग) व स्रवाणकारी कार्यों में प्राथमिकता देना।

(2) सरकार द्वारा अधिक निवेश से आउटसोर्गिग भाउट की समस्या की उल्लिखित।

६) भवजंरचना निवेवा एक
दीवनातिउ व पूंजीगत
निवेश उदा. आधिउ संवेधण
अनुसार वर्तमान वेल्व की
अपने आधुनिकरण के लिए



इस तरह का निवेवा की अवसरमता ।

७) बैंक (NPA की समस्या), पूंजीबाजार (सीमित विकास)

८) PPP मॉडल निजी सार्वजनिक सहयोग से
भवजंरचना विकास को संभव बनाता है।

९) निजी प्रबन्धन प्रौद्योगिकी + सरकारी सुरक्षा
लेना की प्राप्ति उदा. दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट ।

१०) PPP मॉडल से भवजंरचना परियोजनाएँ
समयबद्ध रूप से पूर्ण होती हैं ।

११) परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरता व
वेक्टर क्षमक समाधान प्रबन्धन जयवे (निजी सहभागिता
के कारण) उदा. जयपुर एयरपोर्ट (PPP मॉडल विकास) ।

१२) PPP मॉडल लोक कल्याण (आमजन डेविकरण) व
निजी सहभागिता को व समयबद्धता लेना
सुनिश्चित करती है ।

PPP मॉडल समझ प्रतीकियाँ -

① PPP मॉडल अब तक केवल ब्रह्म अवलोकना परियोजना तक ही सीमित रहे हैं तथा परियोजनाओं पर ध्यान न देना ।

② नियम कालों में असम्पत्ता से परियोजनाओं में फेरी होना

उदा. भारतमाला परियोजना
(2023 तक केवल 40% पूरि)

PPP मॉडल

- BOT मॉडल
- HAM मॉडल
- GPC मॉडल

③ प्रशासनिक जटिलताएँ

• भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी में देरी ।

④ आपरकशी वाली प्रक्रिया उदा. स्विस वीटैज पर अपारकशी का आरोप ।

PPP मॉडल भविष्य की

अवलोकना परियोजना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिससे PPP मॉडल समीक्षा समिति (डेल्टा समिति) अनुशासन अनुसार अधिक समयबद्ध, जनउन्मुख बनाये जाने की आवश्यकता है ।

Q12.

भारत में सुशुद्ध वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इस योजना को सफल बनाने के लिए किन बाधाओं को दूर किया जाना अनिवार्य है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Bring out the role of the 'One Nation-One Ration Card' scheme in ensuring food security for vulnerable sections in India. What obstacles must be overcome to make the scheme a success? (Answer in 250 words) 15

FAO अनुसार, खाद्य सुरक्षा में अभिप्राय सभी वर्गों के लिए हर समय पर्याप्त भोजन की उपलब्धता वधनीयता व पहुँच सुनिश्चित करने के हैं, विशेषतः सुशुद्ध वर्गों के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना

→ इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली

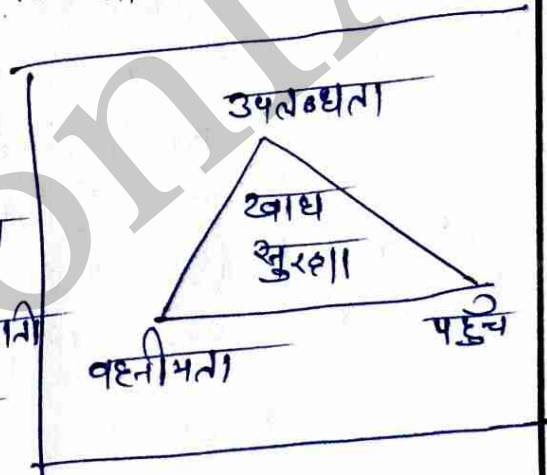
PDS अर्थात् उपभोक्ता खाद्य

मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया गया।

→ उद्देश्य - देश के किसी भी भाग के उचित मूल्य की

दुकान के वायोमेट्रिक पहचान आधार पर अपना शक्ति प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करना।

→ डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा निरन्तर निगरानी सुनिश्चित करना।



HONOR की श्रुति - ① प्रवासी श्रुति को खाद्य पौष्टिकता (आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार भारत की 35 मि. भाषा की प्रवासी श्रुति है) जो विविध वाप्यो में शकान प्राप्त कर सकते हैं।

→ ② डिजिटलीकरण द्वारा खाद्य सामग्री की श्रुति समझा समाधान (शांति कुमार श्रुति ने PDE प्रणाली में 40-50% की श्रुति वात रही)

→ ③ स्मार्ट पीडीएस प्रणाली की श्रुति व शकान सुनिश्चित।

→ ④ संवैधानिक (अनु 47 (पोषण सुरक्षा) व श्रुति (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधि. 2013) के श्रुति की श्रुति सुनिश्चित।

→ ⑤ समावेशन / वृद्धिकरण श्रुति की श्रुति का समाधान (भाषा किं भाषा श्रुति प्रणाली)

→ ⑥ "श्रुति श्रुति अधिकतम शकान" श्रुति अधिक श्रुति श्रुति।

योजना विभाजन में बाधाएँ —

- ① उचित मूल्य की दुकानों के डिजलीकरण की समस्या (लगभग 50% दुकानों पर Pos (पाउंड बैंक लेन) विचारल अ अभाव)।
- ② जघोमिती सीमार (बायोमैट्रिक पहचान) प्रणाली में प्रतियों होने पर प्रदुर्घटन प्रभावित।
- ③ भागजन में जागरूकता अभाव (विशेषतः प्रवासी वर्ग जैसे पंचित गाँवों में)।
- ④ स्मार्ट पीडीएस प्रणाली अर्तगत डिजलीकरण इले साबर सुरक्षा प्रति सुश्लेष्य बनानी है।
- ⑤ FCI (भारतीय खाद्य निगम) की सीमित क्षमता (उत्पादन = 300 मिलियन अण्डारण क्षमता = 150 मिलियन)।

ONOR कई योजना एक प्रतिकारी उद्देश्य है, परन्तु इले भारतनेट योजना (ग्रामीण डिजलीकरण) व बैंक अण्ड अण्डोण के साथ विभाजन कर SDG-2 (अभ्युत्पत्ती अमल्या) अमाधान) प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा सकती है।

Q13.

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए आकलन कीजिए कि क्या एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Assess whether a new industrial policy is required given the central role of the Production Linked Incentive (PLI) scheme. (Answer in 250 words) 15

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना एक विश्वी
शरीर ईकाई उत्पादन व विश्वी पर लाभ प्रदान करने
से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत सफलतापूर्वक
परिणाम रहे हैं (10 लाख करोड़ उत्पादन विश्वी व
8 लाख रोजगार सृजन) भारत सरकार 2024
अनुसार।

PLI केंद्रीय भूमिका - विविध क्षेत्रों व मंत्रालयों
से PLI की सम्बद्धता जैसे स्थानीय उत्पादन
इन्फ्रास्ट्रक्चर, कार्मिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों से
अलग अलग उत्पादन प्रोत्साहन।

→ देवी कम्पनियों के साथ विश्वी कम्पनियों
को भी उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन
प्रदान किया जाना।

→ मेड वन इंडिया के साथ पूरक रूप में महत्वपूर्ण (PLI योजना के विनिर्माण क्षेत्र में FDI में 70% की इति दर्ज की गयी।)

नयी औद्योगिक नीति की आवश्यकता -

- वर्ष 1991 सुधार पश्चात औद्योगिक विकास अनिश्चित व्यापक नीति का अभाव जीले राष्ट्रीय उत्पाद नीति 2012 का सीमित प्रभाव व ~~कुछ~~ क्षेत्रों में सम्बद्धता।
- औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में योगदान का स्तर निम्न बना रहना (वर्तमान GDP में 16-17% भव्य)
- PLI समान विविध हितधारकों सहित एकीकृत उद्विगल की आवश्यकता होना।
- PLI की सीमितताएँ (केवल उत्पादन विहीन समर्थन), जबकि व्यापक उद्योग नीति वृद्धायामी उद्विगल (औद्योगिक अनुसंधान समर्थन, निर्धारित लक्ष्य मुद्दों में समर्थन सुनिश्चित करने में सहायक)

• कृती रोजगार संभावनाओं के लिए (भाषित संवेक्षण 2024 अनुसार भारत के बढ़ते जनसंख्याक कार्यबल के लिए 2030 तक प्रतिवर्ष 80 लाख नवीन रोजगार जैस इति तामों में सृजित करने की आवश्यकता)।

• निम्न आधारित अर्थव्यवस्था व वीरिवत मुख्यश्रुतता में प्रागीदारी (वर्तमान मात्र 40%) की बढ़ाने के लिए सजसुत औद्योगिक आधार निर्माण के लिए आवश्यक)।

PL 3 योजना ने जहाँ औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया है वही एक बहुआयामी औद्योगिक नीति बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को जोड़कर भारत के उदितियन अर्थव्यवस्था तहय में प्राप्ति के इतिशोण में महत्वपूर्ण है।

Q14. भारत में परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों में सुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the prospects and challenges associated with inland waterways as an alternative mode of transportation in India. (Answer in 250 words) 15

अंतर्देशीय जलमार्ग सामान्यतः विविध माध्यमों से नदी मार्गों का जुड़ाव व नदीजल परिवहन को संकथित करता है, जहाँ भारत में व्यापक संभावनाएँ (लगभग 14000 km नौगमन क्षमता) विद्यमान हैं।

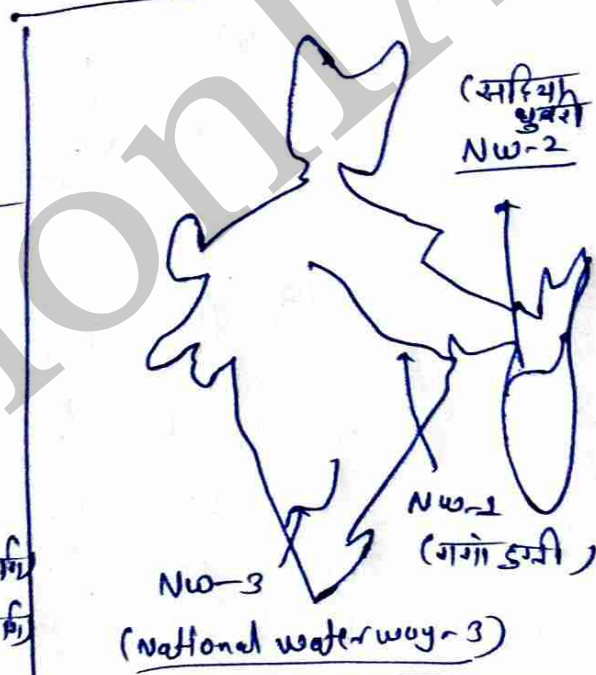
अंतर्देशीय जलमार्गों से जुड़ी संभावनाएँ -

① व्यापक नौगमन मार्ग
(लगभग 14000 km)

② क्वथन दूरान व
यागन दूरान

1 मी क्वथन = 24 km (सड़क मार्ग)

1 मी क्वथन = 204 km (जलमार्ग)



③ अवाप्तन संमालरि सीमित जैसे भूमि अधिग्रहण
अमल्य, इकिक संन्यांजन संमाल्य का अभाष 1

④ आर्थिक विकास से जलमार्गों (इवॉप्तर राज्यों ले
उनेमिक्ती)

- (क) जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन सुनिश्चित करना)
- (ख) पर्यावरणीय रूप से लाभकारी (परिवहन से समुद्रसंचरण क्षतिप्रसवण जैसी समस्याओं का समाव)

अतः जलमार्ग विकास अमरा बाधारे —

- (1) सीमित क्षमता सेवन (वर्तमान सेवन 6000km नौगमन मार्ग का प्रयोग) परिवहन से 2% योगदान)
- (2) नदी से गाढ़ / तलकट / मानसून समस बाध- की समस्या)
- (3) नदी जोड़े परिवोजनाओं का अप्रभावी विभावन, अतः नौगमन मार्ग सीमित घेना)
- (4) समुद्री जीवजन्तुओं पर विपरीत प्रभाव उदा. लक्ष्मीजलमार्ग - 1 के विकास से गंगा नदी डेल्टा आवादी प्रभावित)
- (5) नदी जल प्रदूषण समस्या जैसे तेज विभावन भादि)
- (6) जहाजनिर्माण उद्योग का सीमित विकास व

आइउ परिवहन से साथ कनेक्टिविटी का
अभाव ।

प्रयास — ① राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम का
प्रियान्वन किया जाना ।

→ ② राष्ट्रीय अंतर:देशीय जलमार्ग अधिनियम 2016
अर्थात् 111 राष्ट्रीय जलमार्ग विकास की योजना ।

→ ③ UWA 1 (अंतर:देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) द्वारा
जलमार्ग विकास कार्य की निगरानी ।

→ ④ अंतरराष्ट्रीय उपाओ (जर्मनी से कर शीत नहर
विकास कार्यक्रम) ।

अंतर:जलीय मार्ग अविद्यमान का
परिवहन क्षेत्र है जो जलमार्ग विकास बलेती, सतत
परिवहन, अंतरराष्ट्रीय उपाओ (पन्नामृत) से
सहवपूर्ण भूमिग निभा लकता है, जिनको प्रोत्साहन
दिये जाने की आवश्यकता है ।

Q15.

भारत में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कृषि सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role played by agricultural cooperatives in enhancing farmers' income, promoting agricultural exports, and strengthening the rural economy in India. (Answer in 250 words)

15

सहकारी समितियाँ सदस्यता आधारित सांख्यान
लीन हैं, जो सामुहिक बचत भासा सहयोग व
सांभाजित आर्थिक विकास (सदस्यों के लक्ष्य में) के
क्षेत्र पर कार्य करते हैं व सदस्यों की अल्पकालिक
संगण आवश्यकताओं को पूरि करते हैं।

सहकारी समितियों सम्बन्धित प्रवाधान -

- अनु-19 (अवगत सध बनाने का अधि.)
- अनु-57(B) (नीति निर्देशक सिद्धान्त)
अवगत प्रवाधान।
- भारतीय अधि के विनिमयन में
सहकारी बैंक संरचना।
- PACS (प्राथमिक सहकारी समितियों)
विधि

सहकारी बैंक
↓
राज्य सहकारी
बैंक
↓
जिला सहकारी
बैंक
↓
ग्रामीण
सहकारी बैंक
(PACS)

उद्योग विकास संभावनाओं का बढ़ाना ।

- (3) इन्होंने को सामुदायिक बचत से ऋण अवलंबन का विकास सुनिश्चित करना उदा. सहकारी ऋण द्वारा इन्होंने से लिए बीजमण्डारण प्रणाली का विकास । (बीकॉर्ड फॉरवर्ड रिडेप विकास)

सहकारी समितियों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था

- व केवल ऋण अर्थात् सम्बद्ध गतिविधियों (पशुपालन इति वित्त) द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विवधीकरण सुनिश्चित करना ।

- सहकारी समितियों का कौमन सर्विल सेक्टर को में विकास रखने इन्होंने व आमजन लक्ष विस्तार सेवाओं को पृष्टि सुनिश्चित करना ।

अग्रोउ एलवर्ड समिति द्वारा सहकारी समितियों की बहुआयामी भूमिका पर प्रकाश डाला है इन्हीं अग्रुप इन्होंने किन्न तकनीक प्रोद्योगिकी बाजार लिडेप प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अवसर तंत्र बनाया जा सकता है ।

सरकारी समितियों व इकायों का प्रोत्साहन करना —

→ इकायों को अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति (NABARD द्वारा PACS द्वारा 80% ऋण अथु सीमांत इकायों को)

→ इकायों को खास बीज उर्वरकों को सहायता प्रदान करने से पट्टा चाना ।

→ इकायों के मध्य वयत सहायता का विकास

→ इकायों को उच्च वेतन के रूप में PACS का विकास दिया जाना ।

सरकारी समितियों व नियंत्रण

① इकायों को फार्म इकील आधुनिक प्रणाली से जोड़ना जिससे उत्पादों का उच्च अर्थात् मूल्य प्राप्त हो सके ।

② PACS कार्यक्रम के अन्तर्गत अणुशक्ति प्रणाली का विकास जिससे e-NWR (नेगोशिएटिव वेयरहाउस स्कीम प्राप्ति) व खास प्रोत्साहन

Q16.

देश के राष्ट्रीय पशु के संरक्षण में 'प्रोजेक्ट टाइगर' की सफलता पर टिप्पणी कीजिए। परियोजना के तहत बाघों के समग्र संरक्षण के लिए और क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Comment on the success of 'Project Tiger' in protecting the national animal of the country. What further steps are needed for holistic conservation of tigers under the project? (Answer in 250 words)

15

प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में देश के राष्ट्रीय पशु बाघ की सुरक्षा के लिए प्रारम्भ की महत्वपूर्ण बेहद आयोजित योजना है जो पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) महाधान के तन्वांति है।

प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता

- ① बाघ की आबादी में लगातार वृद्धि (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आधिकरण (NTCA) की रिपोर्ट अनुसार)
- ② विश्व की 20% बाघ आबादी का घर।
- ③ टाइगर रिजर्व की घोषणा कर बाघों का स्वस्थाने स्वरूपों सुनिश्चित करना।
- ④ नवविभाग कमिटी का प्रस्ताव निर्माण द्वारा बाघ



सरकार के लिए बहुआयामी रणनीति बनाना ।

① अंतरराष्ट्रीय तहसी (पीएसबी घोषणा) 2022 के नेतृता बाध आबादी तहसी) के समय के मुद्दे प्राप्ति करना ।

② बाध निगरानी के लिए तकनीक (M-STAMP) (AIDS प्रणाली) का उपयोग करना ।

बाधों के समग्र सरकारों के लिए उपाय -

① बाधों का " फ्लैगशिप स्पेशलिज्म " व डिस्ट्रीन प्रजाति रूप में सरकारों (अन्त प्रजातियों व खाद्य प्रणालियों व खाद्य जात के बाधों की भूमिका का निर्धारण) ।

② स्थानीय आबादी का सर्वेक्षण (मानव परतु संघर्ष को रोकने में सहयोग) ।

③ डिस्ट्रीन प्रजाति (स्थानीय क्षेत्र में बाध आबादी की आवश्यकताओं व जनजातों का सहयोग) ।

उदा. अरुणाचल प्रदेश की मिश्री जनजाती द्वारा
बाघ की पूजा किया जाता है।

(4) उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ परम्परागत ज्ञान
का समावेशन किया जाता है।

(5) बाघ संरक्षण के लिए अनुभव का अन्य प्रजातियों
के पारिस्थितिक संरक्षण के प्रयोग।

एक प्रकार प्रोजेक्ट लागू अर्थात्

बाघ संरक्षण को कृषिजीव अभियोजना (2020-30)

आय सम्बद्ध करते हुए अधिक सहयोगी
समावेशी भाग अपनाया जाता चाहिए।

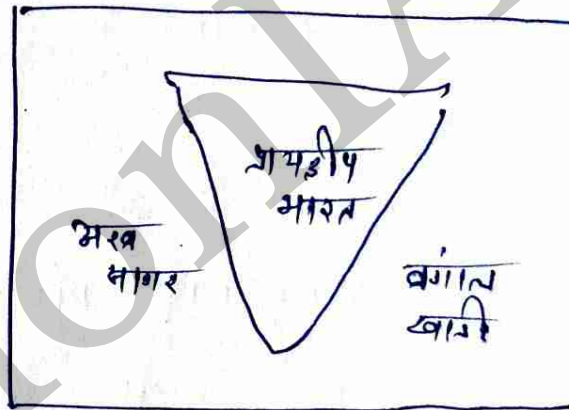
Q17.

यद्यपि बंगाल की खाड़ी में महत्वपूर्ण राज्यों की आपदा तैयारी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी उनकी प्रभावशीलता सीमित रही है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

While the littoral states of the Bay of Bengal have made significant strides in their disaster preparedness, their efficacy has been limited. Discuss. (Answer in 250 words) 15

भारत की 2000km (लगभग) लंबाई वाली अक्षांश रेखा का क्षेत्र है वही प्राकृतिक आपदाएँ (10% चक्रवात) व सुनामी प्रभावों, समुद्री जलस्तर वृद्धि अनेक प्राकृतिक विधमान हैं।

बंगाल की खाड़ी तटवर्ती क्षेत्रों में आपदा तैयारी -



① चक्रवात के लक्ष्य में

- आमजन में चक्रवातों के लक्ष्य में आपदा पूर्व तैयारी का विकास उदा. मॉडर्न आर्माजन।
- मेगाप परियोजनाएँ (बायोकील रूप में विकास)।
- नदीय विनियमन जो न अंतर्गत तटवर्ती क्षेत्रों का विकास व भूमि उपयोग परिवर्तन की निगरानी किया जाना।
- चक्रवात अर्थोपार्जित प्रणाली (IAD द्वारा उत्तर कोडिंग)।

② भूनामी आपदा संदर्भ में

① बंगाल खाड़ी में भूनामी आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास (मुख्य. ईरवाबाद), प्रथी विज्ञान मंत्रालय अंतर्गत क्रियान्वित।

② भूनामी विकट तटीय दैर्घ्योद्देश्य संरचना का निर्माण किया जाना।

③ समुद्री जलस्तर में वृद्धि → बायो कवर का विकास किया जाना।

→ तटीय अपरदन विकट तटीय बनीकरण व तटीय क्षेत्रों से पुनर्वास की नीति।

आपदा तैयारी की सीमितता -

① जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय आपदाओं की आवृत्ति व अभावकता में वृद्धि होना
(IPCC रिपोर्ट अनुसार 1990-2022) हिंद महासागर में चक्रवातों में 50% वृद्धि होना।

- 2) वॉलम अप अप्रोच स्थान पर लैप डाउन अप्रोच को अपनाता ।
- 3) विकास बनाम पर्यावरण की चुनौती (उष्ण क्षेत्रों में मैंग्रोव निवृत्तीकरण की समस्या)
- 4) अपर्याप्त अंतर शैली समन्वय की चुनौती (उदा. 1999 उष्ण उपरसायन)
- 5) आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की सीमाएँ (सूनामी को केवल 1 घण्टा पहले ही चेतावनी)
- 6) मात्रा अंतरिम कार्रवाई जैसी नवनीतरी पहल का अभाव ।
- 7) आपदा प्रबंधन में विपन्न व मानवसंसाधन सीमितता की चुनौती ।

UNODC (संयुक्त राष्ट्र आपदा

जोखिम न्यूनीकरण अभियान) अनुसार आपदा निरूप पूर्व चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक आपदा प्रबंधन भागीदारी व निरंतर तत्परता महत्वपूर्ण हैं, इसी अमूर्त ढंग में आपदा प्रबंधन स्थानीय को भागे बढ़ाया जाना चाहिए ।

Q18.

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वर्तमान में, सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली कौन-सी प्रौद्योगिकियाँ क्वांटम मैकेनिक्स की समझ पर आधारित हैं? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

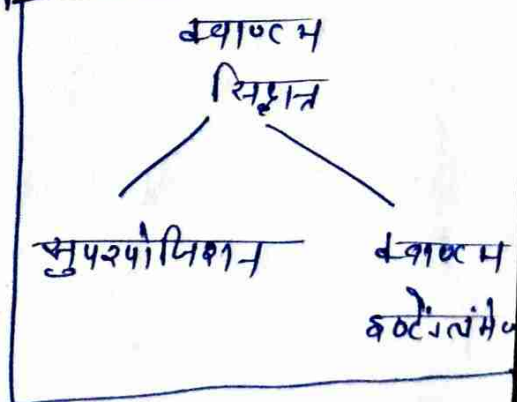
The United Nations proclaimed 2025 as the International Year of Quantum Science and Technology. Which technologies in common use today are based on the understanding of quantum mechanics? What are the steps being taken by India in the field of quantum science and technology? (Answer in 250 words) 15

क्वांटम प्रौद्योगिकी भौतिकी विज्ञान का उप
क्षेत्र है, जो परमाणु उप परमाणु स्तर पर
पदार्थ व ऊर्जा के व्यवहार का अध्ययन करता है।
UN द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान वर
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करना वर्तमान में इसके
महत्व को दर्शाता है।

वर्तमान में क्वांटम प्रौद्योगिकी

अनुरूप →
अनुप्रयोग

→ ① क्वांटम इम्ब्यूटर्सिंग
जो तीव्र अगुना व
क्वांटम स्टेगनोग्राफी



के सिद्धान्त पर "क्यूबिट" के आधार पर

गणना करने में शामिल है।

→ (1) स्वाण्टम संचार प्रौद्योगिकी जो
स्वाण्टम की डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धान्त पर
कार्य करती है जो अधिक सुरक्षित
एण्ड टू एण्ड संचार सुनिश्चित करती है।

→ (2) स्वाण्टम मैट्रिक्स जिसका उपयोग परमाणु
घंटी, घड़ी बनाने में किया जाता है,
स्वाण्टम सुपरपोजिशन सिद्धान्त पर कार्य
करती है।

→ (3) स्वाण्टम सामग्री जिसका उपयोग
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, संचार विद्युत परीक्षण
के विद्युत सर्किट उपकरण तक विविध क्षेत्रों
में किया जाता है जैसे भौतिकी में नोबल
पुरस्कार स्वाण्टम इंस (भट्टाचार्य न इतिम
स्वाण्टम कण्ड के क्षेत्र में दिया गया।

→ (4) अनुसंधान नवाचार के क्षेत्र में स्वाण्टम
प्रभाव का उपयोग अन्तःराष्ट्रीय अनुसंधान
सुपरनायकता, सूक्ष्मप्रतिरोधकता जैसे क्षेत्र में किया जाता है।

ब्याज विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के प्रयास —

① नेशनल ब्याज मिशन (विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
अंतर्गत 30 वषीय परियोजना)

1000 व्यक्ति प्रोसेसिंग युनिट का विकास लक्ष्य ।

② Queue पहल (ब्याज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में
नवाचार व अनुसंधान विकास से सम्बन्धित)

③ नेशनल सुपर इम्प्युटिंग मिशन (नेशनल नैटवर्क
नेटवर्क) अंतर्गत ब्याज इम्प्युटर विकास
पर लक्ष्य ।

ब्याज प्रौद्योगिकी क्षेत्र में
उभरता क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएँ विद्यमान
है अंतरराष्ट्रीय सहयोग व राष्ट्रीय अनुसंधान
विकास अकादमी के उन्नतिकरण से लाभ रक्ष
क्षेत्र में विकास आवश्यक है ।

Q19.

प्रमुख संस्थागत और नीतिगत परिवर्तनों ने भारत में रक्षा के स्वदेशीकरण, घरेलू पूंजी खरीद (Domestic Capital Procurement) और रक्षा संबंधी निर्यात को बढ़ावा दिया है। इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों और अभी भी विद्यमान मुद्दों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Key institutional and policy changes have spurred defence indigenisation, domestic capital procurement and defence exports in India. Discuss the measures adopted by the Government in this respect and the issues that still persist. (Answer in 250 words)

15

SI PR1 द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार भारत द्वारा प्रथम बार कोविड 25 रक्षा निर्यातकों की सूची में शामिल हुआ है साथ ही रक्षा आयात क्षेत्रों में विपरीत रूप सुनिश्चित किया है।

भारत के प्रयास — निर्यात लक्ष्य — 2025 तक 5 वि. डॉलर निर्यात।

① प्रमुख संस्थागत प्रयास — ① चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे मकीन पर (डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अफैयर्स) का गठन किया जाना।

② रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा रक्षा खरीद उद्दिष्टों के अधिक सरल बनाया जाना।

③ रक्षा अधिग्रहण सम्बंधित नीति में सरकार के स्वदेशीकरण सूची अपनाकर घरेलू

स्तर पर रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन दिया
जाता ।

(प) IDEX सूचना पॉलिसी, अदिती (ADITYA) जैसे
नवोन्मुखी पहलुओं से रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान
विकास को बढ़ावा ।

(इ) प्रौद्योगिकी विकास कोष के गठन के साथ
निसर प्रौद्योगिकी उन्नयन पर बल ।

(ई) रक्षा मायात को बुलना संयुक्त उत्पादन पर
बल उदा. भारत इस द्वारा प्रमोत मिलान
निर्माण ।

(क) DRDO जैसे शीघ्र रक्षा विकास संगठन के
निर. की राधवन भूमि का गठन किया जाता ।

(ख) उच्चरी प्रौद्योगिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग
जैसे भारत यूएसए मध्य (AUSOIX) पहल ।

वर्तमान में विद्यमान प्रणितियाँ —

(1) DPec (रक्षा मार्कजनिउ अधिनी) का रक्षा
उत्पादन पर कर्तव्य होना ।

- ② भारतीय रक्षा व्यय का 60% अधिक व्यय
सजल व्यय के रूप में ।
- ③ प्रशासनिक सुनौतियों (भीतर तक अधिग्रहण
में 6-7 वर्षों के समय)
- ④ भारतीय रक्षा उपकरण का IPR (कॉपीराइट)
मुख्यतः विदेशी कर्मों के पास लेना ।
- ⑤ सीमित रक्षा बजट (GDP का लगभग 2% ही)
- ⑥ अनुसंधान विकास पर सीमित व्यय (GDP का
0.67% लगभग)

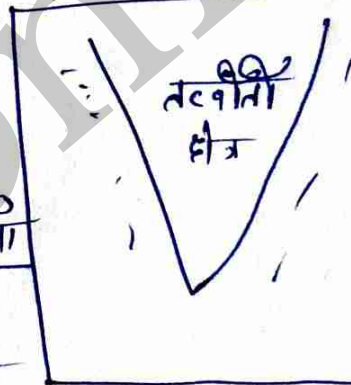
रक्षा क्षेत्र में 70% तक विदेशी
निर्देश, GOCO मॉडल जैसे विकल्पों के साथ
सहकर सशस्त्र अनुसंधान अनुसार रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

Q20. गैरकानूनी गतिविधियों के प्रति भारत के तटों की सुभेद्यता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तटीय सुरक्षा के लिए मौजूदा सुरक्षा प्रणाली पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The vulnerability of India's coasts to unlawful activities poses significant threats to national security. Discuss the current security system in place for coastal security. (Answer in 250 words) 15

7000 km लम्बी तटवर्ती क्षेत्र भारतीय
आन्तरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है,
जो हिन्द महासागर से भारत की निरन्तर
सुरक्षा प्रदाना भूमिका के अर्थ में अत्यधिक
महत्वपूर्ण हो जाती है।

तटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियाँ



① संगठित समुद्री अपराध

की समस्या (उदा. सोमालिया में समुद्री पायरेसी
की गठनरि)।

→ ② तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा बलों के

मध्य समन्वय की समस्या (उदा. राज्य मरीन
पुलिस, तटरक्षा बलों के मध्य वार्ह्याप)।

- ⑤ समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में चीनी दस्त्रकोप की समस्या (मोटियों की चारा की नीति)
- ⑥ तटवर्ती क्षेत्रों में शोध संस्थान गतिविधियों की समस्याएँ।
- ⑦ माकड़ परिवार संरक्षकों की समस्या (गोल्डन प्राइम गोल्डन डीलेट मध्य क्षेत्र)
- ⑧ राज्य प्रायोजित आतंकवाद समस्या जैसे पारिस्थितिक समर्थित समुद्री उहेली इती विध्वंसियों द्वारा होमज जलजन्मक मध्य की शोका जाना।
- ⑨ बढ़ता समुद्री जल स्तर से तटीय अपवदन व तटीय भावादी की पुर्नवास की समस्या।
- ⑩ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंक (स्वज नहर अंक) जैसी पुनीतियों।

तटीय सुरक्षा के लिए मौजूदा योजनाएँ -

त्रिस्तरीय सुरक्षा योजनाएँ -

तटवर्ती क्षेत्र (12nm) तक = राज्य स्तरीय पुनीत

12nm - 200nm तक = संरक्षित क्षेत्र

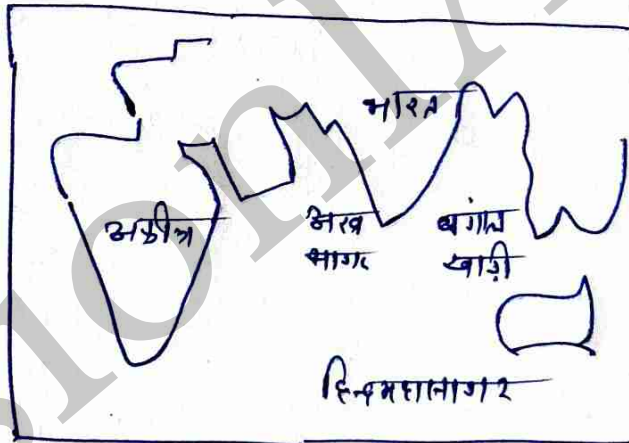
200 nm से 0.1 माइक्रोमीटर = भारतीय नीलेना
(समुद्र तटरी बन्ध)

① संयुक्त समुद्री अभ्यास (सी विजन का आयोजन)

→ IFC-20R (इण्डियन ओशन कॉमिशन प्रयुक्त
सेक्टर) का निरंतर तटवर्ती सूचना निगरानी)

→ तटवर्ती राज्यों में डफ्तर रडार प्रणाली का
विकास दिया जाना

→ "महालागार" व "लागार" जैसी
पहलों के माध्यम
से मानवीय व
आपदा संकट
सहयोग।



→ वृष्टपणीय स्तर पर - 20R (इण्डियन ओशन रिम
एसीमिलेशन), 20C (इण्डियन ओशन कॉमिशन) के
सहयोग।

इस प्रकार समुद्री अभ्यास का विजन 2047

भारत हिन्द महासागर क्षेत्र में शुद्ध सहयोग
के लिए निरंतर प्रयासरत है।